ECO – Semester VI
~~2016 Exam~~ Paper-(XIII)
Public Finance

1) सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अन्तर करें ?

What do you mean by public finance? Distinguish between public finance and private finance.

राजस्व या लोकवित्त अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। आधुनिक समय में राजस्व देश की आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र बिन्दु बन गया है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने न्यूनतम राजकीय हस्तक्षेप के पक्ष में थे। उन्होंने स्वतन्त्र नीति (Laissez faire policy) के पक्षधर थे परन्तु सन 1930 की आर्थिक महामन्दी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बगैर राजकीय हस्तक्षेप के आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी निम्न उत्पादन आदि को दूर नहीं किया जा सकता यही कारण है की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Prof. J. M. Keynes, Hansen, Prof Lerner आदि ने राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक बताया और वर्तमान समय में राजस्व के क्षेत्र का विस्तार हुआ और सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएँ राजस्व के इर्द- गिर्द घूमती रहती हैं।

साधारण अर्थ में, लोक वित्त का अर्थ सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक संस्थाओं की वित्तीय लेन देन को ही राजस्व कहा जाता है। परन्तु राजस्व का यह सीमित अर्थ है। राजस्व के ~~अन्त~~ सम्बन्ध में राज्य के वित्तीय प्रबन्ध का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्रीयों ने इसकी कई परिभाषाएँ दी हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं।

According to Dr Dalton के अनुसार "Public Finance Deals with the income and Expenditure of Public Authorities and with the manners in which the one is adjusted to the other."

Findlay shiras के अनुसार "The study of the Principles underlying the spending and raising of funds by public authority."

Mehta and Aggrawal के अनुसार — "Public finance is the Constitutes a study of the monetary and Credit Resources of the State."

इस प्रकार ऊपर दिए गए परिभाषाओं से स्पष्ट है की राजस्व अर्थशास्त्र के अन्तर्गत सरकार की आय-व्यय से सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन का समायोजन किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अन्तर्गत वित्तीय प्रशासन, लेखा जाँच और वित्तीय नियन्त्रण को भी शामिल किया जाता है।

Difference between private finance and public finance.

(i) आय व्यय के समायोजन में अन्तर — निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में अन्तर आय व्यय में समायोजन (adjustment) को लेकर किया जाता है। निजी व्यक्ति अपनी आय देखता है और इसके अनुसार अपनी व्यय को निर्धारित करता है।

जबकि राज्य पहले यह तय करता है की उसे विभिन्न मदों पर कब कितना और कैसे खर्च करता है। अतः व्यय के अनुसार आय के साधनों पर विचार करता है।

उद्देश्यों में अन्तर (Difference in Aims) — जहाँ पर निजी आय या व्यय का उद्देश्य तत्कालिक उपलब्धियों को प्राप्त करना होता है जबकि राज्य की आय व्यय की परिधि दीर्घकाल तक होती है।

ऋण की सुविधा में अन्तर — जहाँ तक निजी वित्त का सवाल है जब एक व्यक्ति का खर्च उसकी आय से अधिक होती है तो वह सरलता से ऋण की व्यवस्था नहीं कर पता उसे ऋण प्राप्त करने की सीमा उसकी साख पर निर्भर करती है। जबकि सरकार को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है क्योंकि सरकार की साख अधिक होती है।

राज्य का निजी की तुलना में अधिक प्रभुत्व — राज्य को शक्तिशाली होने के कारण वह लोगों की सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है और उसको हड़प सकता है। भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीय करण इसका उदाहरण है। जबकी नीजी व्यक्ति की सीमा सीमित है।

भविष्य के लिए आयोजन में अन्तर — निजी व्यक्ति के लिए भविष्य सरकार की तुलना में आयोजन करना अधिक सरल है जबकि राज्य के सामने प्रतिदिन नयी-नयी समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे अकाल, महामारी राष्ट्रीय संकट आदि।

(vi) बजट की प्रकृति में अन्तर — निजी व्यक्ति अपनी कुशलता इसी में मानता है की यदि उसका बजट अतिरेक है तो वह प्रसन्न होता है लेकिन सार्वजनिक बजट संतुलित होना अच्छा माना जाता है और कभी Deficit finance घाटे का बजट बनाना भी बुद्धिमानी माना जाता है।

(vii) गोपनीयता का अन्तर — दोनों ही वित्त व्यवस्था में गोपनीयता अंतर पाया जाता है।

— इस प्रकार ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि लोकवित्त या सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में कई अन्तर है। हालांकि गौर से देखा जाए तो दोनों के आधारभूत अन्तर में समानता पाई जाती है जहाँ पर नीजी व्यक्ति का सम्बन्ध आवश्यकताओं से सम्बन्धित है वहीं पर सार्वजनिक वित्त में सरकार को सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखना पड़ता है।

Q2. अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। ("Maximum social advantages theory of public finance)".

or

राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह जिसके अंतर्गत राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है।"

उत्तर ⇒ अधिकतम सामाजिक लाभ या कल्याण का सिद्धांत राजस्व का एक आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से Prof Dalton तथा Pigoue है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना होना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में सार्वजनिक वित्त का महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है और राजकोषीय क्रियाएँ आर्थिक जीवन में बहुत हद तक प्रभावित करती है। जहाँ एक ओर सरकार जनता पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है और दूसरे तरफ उस आय को जनता के कल्याण के कार्य पर खर्च करती है। अतः Dalton ने अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के आधार पर आय को व्यय करने की बात कही है उन्हीं के शब्दों में—

"The best system of public finance is that which secures the maximum social advantages from the operation which it Conducts".

अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के अनुसार अपनी आय को खर्च करे तो समाज को अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सकता है। यदि सरकार के किसी काम से जनता को आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो उसे उपयुक्त माना

जाता है और इसके विपरीत होती है तो अनुपयुक्त माना जाता है। क्योंकि सरकार जनता पर कर लगाती है जिससे जनता में असंतुष्टि होती है। जो व्यक्ति कर देते हैं उन्हें कष्ट अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति पर खर्च किया जाता है उन्हें संतुष्टि मिलती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जाती है की असंतुष्टी की तुलना में संतुष्टी या लाभ अधिक मात्रा में हो। यह तभी सम्भव है जब की खर्च से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कर दाता के सीमांत अनुपयोगिता के बराबर हो इसलिए करों एवं व्ययों में बढ़ाने का आधार सीमा यही होती है।

इस सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित तालिका द्वारा किया जा सकता है।

कर की इकाई	कर की प्रत्येक इकाई से होने वाला सिमांत अनुपयोगिता	व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सामाजिक लाभ (उपयोगिता)
1	25	110
2	50	90
3	60	85
4	75	75
5	90	65
6	120	50
7	160	35.

ऊपर दिए गए तालिका से स्पष्ट है की अधिकतम सामाजिक कल्याण उस बिन्दु पर होगा जहाँ पर टैक्स (कर) की एक इकाई लगाने से होने वाला त्याग खर्च की जाने वाली एक ईकाई से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता के बराबर हो जाए। तालिका में चौथी ईकाई पर सीमांत उपयोगिता तथा अनुपयोगिता बराबर है।

इस नियम की व्याख्या नीचे दिए गए रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

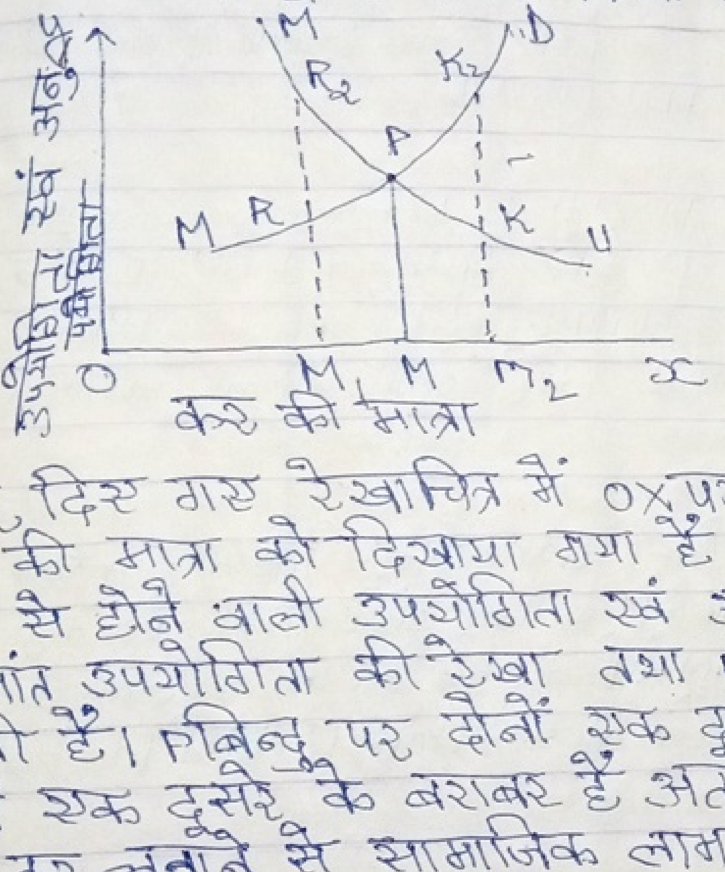

ऊपर दिए गए रेखाचित्र में OX पर सार्वजनिक व्यय तथा कर की मात्रा को दिखाया गया है OY पर सार्वजनिक व्यय से होने वाली उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को M.U. सीमांत उपयोगिता की रेखा तथा M.D. सीमांत अनुपयोगिता बताती है। P बिन्दु पर दोनों एक दूसरे को काटती है अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर है अतः चित्र से स्पष्ट है की OM कर लगाने से सामाजिक लाभ अथवा कल्याण अधिकतम होगा।

अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत एक आधारभूत सिद्धांत है परन्तु फिर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुछ कठिनाईयाँ भी है जो निम्नलिखित है।

1) सीमांत उपयोगिता को मापना कठिन है — इस नियम में सबसे बड़ी कठिनाई यह है की सार्वजनिक व्यय करने से जनता को कितनी मात्रा में सीमांत उपयोगिता मिलती है ठीक उसी तरह सीमांत अनुपयोगिता को मापना कठिन है।

2) कर भार का अनुमान (Tax burden) का अनुमान लगाना कठिन है। — इस नियम की दूसरी बड़ी कठिनाई यह है की प्रत्येक करों का भार अलग अलग होता है परन्तु इसकी भार को मापना कठिन है।

3) गैर आर्थिक तत्वों का प्रभाव (Non-Economic factors) — राजस्व की क्रियाएँ पर गौर किया जाए तो आर्थिक तत्व के अलावे कुछ गैर आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है जिससे इसका सही-सही माप करना कठिन हो जाता है।

4) उपयोगिता तथा अनुपयोगिता (utility and disutility) में सम्बन्ध बताना कठिन :- जिस तरह से उपयोगिता और अनुपयोगिता को मापना कठिन है ठीक उसी तरह इन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है।

5) अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोण में अन्तर — कर लगाने से अल्पकालीन दृष्टिकोण से जो लाभ प्राप्त होते हैं वही दीर्घकालीन दृष्टिकोण से हानिकारक भी हो सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त बातों से स्पष्ट है की अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं फिर भी राजकीय व्यवस्था की सर्वोत्तम प्रणाली वही है जो देश के उत्पादन में वृद्धि करके इसके वितरण में भी सुधार करे। डॉ डाल्टन ने ~~xxxx~~ अपनी बातों को सुधार करते हुए कहा है की "The principle obvious, simple and far reaching ~~xox~~ though its practical application is often very difficult." एक यूनानी कहावत के रूप में कहा गया है की "सरल चीजें नहीं बल्कि कठिन चीजें सुन्दर हुआ करती हैं"